सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन

चर्चा में क्यों ?

- **सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन** (SCBA) द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अदालत के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और उन्हें सुलभ और समावेशी बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया।
- **उदेश्य-** न्यायपालिका की मुख्य चुनौती **"न्याय तक पहुंच"** में आने वाली बाधाओं को दूर करना है और न्याय देने की अदालत की क्षमता में विश्वास पैदा करना है।

प्रमुख बिंदु

- बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु **"सुप्रीम कोर्ट के विस्तार की योजना"** का विवरण दिया गया, जिसके तहत 27 अतिरिक्त अदालतों, 51 न्यायाधीशों के कक्ष, 4 रजिस्ट्रार कोर्ट कक्ष, 16 रजिस्ट्रार कक्ष और वकीलों और वादियों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाओं को समायोजित करने के लिए एक नई इमारत का निर्माण शामिल है।

- इसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा: पहले चरण में, संग्रहालय और एनेक्सी भवन को ध्वस्त किया जाएगा ताकि 15 कोर्ट रूम, न्यायाधीशों के कक्ष, SCBA पुस्तकालय, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के कार्यालयों के लिए एक नई इमारत का निर्माण किया जा सके।
- दुसरे चरण में, 12 कोर्ट रूम, जजों के चैंबर, रजिस्ट्रार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के लिए लाउंज को समायोजित करने के लिए और नए भवन के अन्य हिस्से बनाने के लिए मौजूदा कोर्ट परिसर के कुछ हिस्से को तोड़ दिया जाएगा।
- नई इमारत "न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाली जगह प्रदान करने के अलावा, लोगों की संवैधानिक आकांक्षाओं, विश्वासों और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेगी"।
- "न्याय में प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण लागू किया जायेगा।"
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक निर्णय लेने और लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर एक हैंडबुक जारी की जाएगी।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

- यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करता है। इसके सदस्य भारत में वकीलों के बीच से चुने जाते हैं और इस तरह भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके नियामक कार्य करता है।
- यह उन विश्वविद्यालयों को कानूनी शिक्षा और अनुदान-मान्यता के लिए मानक भी निर्धारित करता है जिनकी कानून की डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी।